

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3084
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार सुरक्षा सहयोग

3084. श्री के. ई. प्रकाश:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विदेशों में, विशेष रूप से संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारत की राजनयिक उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क) हाल के वर्षों में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ आपसी हित के अनेक क्षेत्रों में अनेक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में जन संपर्क और जुड़ाव बढ़ाना तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है।

(ख) विदेशों में भारतीयों का कल्याण और संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशन/केंद्र भारतीयों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर कॉल, वॉक-इन, ई-मेल, सोशल मीडिया, 24x7 हेल्पलाइन, ओपन हाउस, मदद पोर्टल आदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं और आपातकालीन या संकट की स्थिति के दौरान, विदेशों में स्थित मिशन/केंद्र सक्रिय रूप से संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय नागरिकों तक पहुंचते हैं और उन्हें कांसुलर सहायता, भोजन, आश्रय, दवा और भारत वापसी मार्ग प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं।

(ग) सरकार की व्यापक विदेश नीति का उद्देश्य विदेशों में भारत की उपस्थिति को अधिकतम करना है। 2014 से, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में कई नए भारतीय राजनयिक मिशन स्थापित किए गए हैं, ताकि इन क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति और पहुंच का विस्तार किया जा सके।
